कैलाशचंद्र

बनाम

एम. पी. का राज्य

30 नवंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत, तरण चटर्जी और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे.]

मध्य प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915-एस. 46 और 47-के तहत अपराध ट्रक के माध्यम से किया गया अधिनियम-ट्रक की जब्ती अदालतों ने पाया कि ट्रक का मालिक इसकी कमी को स्थापित करने में विफल रहा अपराध की जानकारी-ज़ब्त करने का अधिकार-आयोजितः बोझ

मालिक पर अपराध होने की जानकारी की कमी स्थापित करने के लिए संपत्ति, मालिक उसी को स्थापित करने में विफल रहा है, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है ज़ब्त किया जाए-हालाँकि, मामले के तथ्यों में, ज़ब्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के बदले में जुर्माना लगाया जाता है। 452 .

पुलिस ने विदेशी माल के साथ अपीलार्थी का ट्रक जब्त किया शराब। ट्रायल कोर्ट ने एम. पी. की धारा 34 के तहत ट्रक के चालक को दोषी ठहराया।

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915। निचली अदालत ने भी ज़ब्त करने का आदेश पारित किया अधिनियम की धारा 46 के तहत ट्रक का, यह

अभिनिर्धारित करते हुए कि अपराध मालिक की जानकारी में था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पुष्टि की कि

विचारण न्यायालय का निष्कर्ष। उच्च न्यायालय ने नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि तथ्यात्मक

निचली अदालतों द्वारा स्थिति पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया था।

वैकल्पिक रूप से इसने तर्क दिया कि जब्ती के बदले में, धारा 47 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए,

पकड़नाः 1. एम. पी. उत्पाद शुल्क की धारा 46 के प्रावधान के अनुसार अधिनियम, 1915 स्थापित करने का भार संपत्ति के मालिक पर है। कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि इस तरह का अपराध किया जा रहा था प्रतिबद्ध था या होने की संभावना थी। यह प्रावधान करता है कि कोई जानवर नहीं,गाड़ियाँ, जहाज, राफ्ट और अन्य परिवहन उत्तरदायी होंगे जब्ती, यदि यह साबित हो जाता है कि वे संपत्ति नहीं हैं अपराधी और यदि मालिक यह स्थापित करता है कि उसके पास कोई कारण नहीं है उनका मानना है कि ऐसा अपराध किया जा रहा था या होने की संभावना थी।

निचली अदालत, पहली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने अपनी कमी को स्थापित नहीं किया है

ज्ञान। [पैरा 9 और 10] [782-जी; 783-ए, बी]

2. जहाँ तक भुगतान से संबंधित वैकल्पिक प्रस्तुति का संबंध है जब्ती के बदले में जुर्माने का संबंध है, मजिस्ट्रेट ने नहीं किया है अपीलार्थी के विकल्प का संकेत दिया। मामले के तथ्यों पर, यह निर्देश दिया जाता है कि वाहन को अपीलार्थी को जारी कर दिया जाएगा जुर्माने के रूप में Rs.30,000/- की राशि का भुगतान।

[पारस 11 और 12] [783-बी, सी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 1649/2007

उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 16.5.2006 से मध्य प्रदेश का न्यायालय, सी. आर. एल. में इंदौर की पीठ। आर. नहीं. 305/2005 अपीलार्थी की ओर से पुनीत जैन, एच. डी. थानवी और प्रतिभा जैन। सी. डी. सिंह, मेरुसागर सामंताराय और सनी चौधरी उत्तरदाता। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में चुनौती एक विद्वान एकल द्वारा पारित आदेश के लिए है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ के न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः 26.04.1996 पर, पंजीकरण No.MOU 9470 वाले ट्रक में, अपीलार्थी का चालक अनोखीलाल पोरवाल 244 डिब्बों को ले जा रहा था। प्रत्येक में 48 चौथाई-रम ड्राइगिन, बीयर और विदेशी शराब होती है। रात में लगभग 1 बजे ट्रक गाँव नागनघाट मेघनगर से गुजर रहा था। पी. एस. काकनवाना के स्टेशन हाउस अधिकारी को सूचना देने वाले से ट्रक के गुजरने की जानकारी मिली।

जिसे उन्होंने ट्रक को नागनघाट बैरियर पर रोका और ट्रक [2007] 12 एस. सी. आर. को जब्त कर लिया। विदेशी शराब के भंडार के साथ। अपराध No.62/96 दर्ज किया गया था

एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम 1915 की धारा 34 के तहत काकनवानी पी. एस. (संक्षेप में) अधिनियम ') और उचित जांच के बाद, के समक्ष आरोप पत्र दायर किया ड्राइवर अनोखीलाल पोरवाल के खिलाफ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कराया। ट्रक अपीलार्थी कैलाशचंद्र के स्वामित्व में था और अभी भी है।

ट्रायल कोर्ट, ट्रायल पूरा होने के बाद, दिनांक 1 के फैसले द्वारा आरोपी को दोषी ठहराया और उसे एक साल के लिए आर. आई. और जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माने का भुगतान न करने पर 2,000/- रुपये का आर. आई. दो के लिए और भुगतना होगा।

अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन निचली अदालत इससे संतुष्ट नहीं हुई और ट्रक को जब्त करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी कैलाशचंद्र ने अपील (सी. आर. आई.) प्रस्तुत की। ए. नं. 25/2001) जिसके द्वारा

निचली अपीलीय अदालत ने दिनांकित आदेश द्वारा मामले को वापस भेज दिया 29.11.2001 इस आधार पर कि सुप्रतदार को व्यक्तिगत रूप से ट्रक को जब्त करने का नोटिस नहीं दिया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने मिस्क को पंजीकृत किया। आपराधिक मामला No.34/2000 और फिर से सुप्रतदार/अपीलार्थी को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अपना जवाब प्रस्तुत किया और खुद के साथ-साथ गवाह ओंकार से भी पूछताछ की।

ट्रायल कोर्ट ने फिर से ट्रक को जब्त करने का आदेश पारित किया 07.03.2000. इस आदेश को अपीलार्थी द्वारा सी. आर. एल. में फिर से

चुनौती दी गई थी। A.No.24/03 दिनांकित 12.09.2003 निर्णय द्वारा। इस निर्णय/आदेश के विरुद्ध,

अपीलार्थी कैलाशचंद्र ने दाखिल किया। 773/03 उच्च से पहले अदालत और उच्च न्यायालय ने मामले को इस आधार पर निचली अपीलीय अदालत में वापस भेज दिया कि निचली अपीलीय अदालत ने नहीं किया था। कानून के किस प्रावधान (चाहे नया हो या पुराना) के तहत अपील का उल्लेख किया गया है दायर किया गया था और नए सिरे से निर्णय लेने के लिए और यह देखने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश भी जारी किया गया था कि क्या आरोपी अनोखीलाल ने कोई अपील दायर की है और यदि कोई दायर की गई है,

उस अपील का भाग्य क्या था। निचली अपीलीय अदालत, की दृष्टि में उच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देश ने दोनों पक्षों को सुना

विस्तार से और सभी मुद्दों का फैसला किया। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था अवैध परिवहन के संबंध में आरोपी अनोखीलाल के खिलाफ पुलिस 26.04.1996 पर ट्रक में विदेशी शराब। अतः, का प्रावधान अधिनियम की धारा 46 का ज़ब्त, लागू होगा और संशोधित प्रावधान कैलाश चंद्र बनाम

धारा 47 और 47-ए के स्थान पर एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम (अधिनियम सं. XXII

2000 का) जो 04.08.2000 से लागू हुआ, लागू नहीं होगा और अंतिम होगा

अधिनियम की धारा 46 के साथ आपराधिक मामले का निपटान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 452 (संक्षेप में 'Cr.P.C')। लागू होगा। निचली अपीलीय अदालत ने दलीलों को स्वीकार नहीं किया लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तावित कि अधिनियम का संशोधित प्रावधान, धारा 47-ए और बी लागू होंगी क्योंकि निर्णय इसके बाद पारित किया गया था। 2000 के संशोधित अधिनियम का प्रवर्तन। उच्च न्यायालय के अनुसार निचली अपीलीय अदालत ने इस मुद्दे पर सही फैसला किया था क्योंकि जब्ती एक दंडात्मक प्रावधान है और इसलिए, एक लंबित मामले में, पूर्व संशोधन के लिए, संशोधित प्रावधान लागू नहीं होगा और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 2000 के संशोधित अधिनियम में नए अधिनियमों को लागू करने के लिए विशिष्ट प्रावधान और अन्य वस्तुओं को जब्त करने का प्रावधान, जिसमें शामिल हैं किसी लंबित मामले में अपराध।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का रुख था कि वह था केवल ट्रक का मालिक और उस समय ट्रक में मौजूद नहीं था अवैध शराब के साथ जब्ती। चालक अनोखीलाल पोरवाल उसके बिना सहमति और अनुमति ने ट्रक ले लिया और इसलिए, मालिक कर सकता था दंडित नहीं किया जाता है।

5. उच्च न्यायालय ने नोट किया कि विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय

न्यायालय ने इस पहलू पर विस्तार से विचार किया था और समवर्ती रिकॉर्ड किया था। इस तथ्य के निष्कर्ष कि ट्रक के मालिक की जानकारी के बिना, जैसे भारी मात्रा में विदेशी शराब और वह भी गुजरात की ओर, जहाँ शराब का व्यापार प्रतिबंधित है, यह संभव नहीं था। तदनुसार, संशोधन याचिका खारिज कर दी गई।

6. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत किया कि नीचे के न्यायालयों ने तथ्यात्मक स्थिति की सराहना नहीं की है सही है। वैकल्पिक रूप से यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 47 के तहत, जैसा कि यह था संशोधन से पहले, मामले के तथ्यों पर लागू होता था और जब्ती के बदले जुर्माना लगाया जा सकता है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तथ्यात्मक निष्कर्षों को इस निष्कर्ष पर दर्ज किया गया है कि याचिका ली गई है स्वामी द्वारा-अपने ज्ञान की कमी के बारे में अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। जहाँ तक वैकल्पिक प्रस्तुति का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2007] 12 एस. सी. आर.

जब्ती या विकल्प में वस्तु के मालिक को उत्तरदायी देने के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में जब्ती के बदले में इस तरह के जुर्माने का भुगतान

करने का विकल्प जब्त किया जाए उचित सोचता है। इस विकल्प का सुझाव नहीं दिया गया था और अपीलार्थी ने भी यह रुख अपनाया कि ज़ब्त करने का आदेश अनुचित था।

8. धारा 46 और 47 (संशोधन से पहले) निम्नानुसार हैः

46. जब्त करने के लिए कुछ चीजों का दायित्वः

(1) जब भी कोई अपराध किया गया हो जो दंडनीय हो। इस अधिनियम के तहत, मादक पदार्थ, अभी भी, बर्तन, लागू करते हैं या ऐसा उपकरण जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया हो। जो किया गया है वह ज़ब्त करने योग्य होगा।

(2) कानूनी रूप से आयातित, परिवहन, निर्मित कोई भी मादक पदार्थ, किसी के साथ या उसके अतिरिक्त कब्जे में रखा गया या बेचा गया उप-धारा (1) के तहत ज़ब्त करने योग्य मादक पदार्थ, और मादक पदार्थ, ,बर्तन ,उपकरण उपरोक्त है या पाए जाते हैं, और अन्य सामग्री यदि कोई हो, पात्र या पैकेज जिसमें वे पाए जाते हैं या पाए जाते हैं, और जानवर, गाड़ी, बर्तन, राफ्ट या अन्य परिवहन का उपयोग किया जाता है उसी को ले जाने में, इसी तरह ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। बशर्ते कि कोई पशु, गाड़ी, बर्तन, राफ्ट और अन्य परिवहन न हो यदि यह साबित हो जाता है कि वे नहीं हैं तो वे जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। अपराधी की संपत्ति और यदि उसका मालिक यह स्थापित

करता है कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा था या था

प्रतिबद्ध होने की संभावना है। जब्ती का आदेश-(1) जहां किसी भी मामले में उसके द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। मजिस्ट्रेट निर्णय लेता है कि कुछ भी जब्त करने के लिए उत्तरदायी है धारा 46, वह या तो जब्त करने का आदेश दे सकता है या ज़ब्त की जाने वाली चीज़ का, भुगतान करने का विकल्प, के बदले में ज़ब्ती, ऐसा जुर्माना जो मजिस्ट्रेट उचित समझे।

9. धारा 46 के प्रावधान के अनुसार, बोझ पर है संपत्ति का मालिक यह स्थापित करने के लिए कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा था या किए जाने की संभावना थी। यह प्रावधान है कि कोई भी जानवर, गाड़ी, जहाज, राफ्ट और अन्य परिवहन नहीं होगा यदि यह साबित हो जाता है कि वे उनकी संपत्ति नहीं हैं, तो वे जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। अपराधी और यदि मालिक यह स्थापित करता है कि उसके पास विश्वास करने का कोई कारण नहीं है

कि ऐसा अपराध किया जा रहा था या होने की संभावना थी। जैसा कि उल्लेख किया गया है। ऊपर, मालिक को उपरोक्त तथ्यों को स्थापित करना होगा।

10. विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने अपने ज्ञान की कमी को स्थापित नहीं किया है।

11. जुर्माने के भुगतान से संबंधित वैकल्पिक प्रस्तुति पर आते हुए जब्ती के बदले में हम पाते हैं कि मजिस्ट्रेट ने संकेत नहीं दिया था अपीलार्थी का विकल्प।

12. मामले के तथ्यों पर, हम निर्देश देते हैं कि वाहन होगा जुर्माना के रूप में Rs.30,000/- की राशि के भुगतान पर अपीलार्थी को जारी किया जाता है।यह राशि आज से चार महीने की अवधि के भीतर जमा की जानी है। यदि उपरोक्त समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो यह आदेश नहीं होगा। संचालन और अपील को खारिज माना जाएगा।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आटिफिशियल इंटेलजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी स्वाती पारीक आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।